भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4584 का उत्तर

महाराष्ट्र में लंबित रेल परियोजनाएँ

4584. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुंबई-नागपुर हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) वर्ष 2023 में प्रस्तुत की गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी अनुमोदन अभी भी लंबित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और देरी के क्या कारण हैं तथा अनुमोदन की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ग) 309 किलोमीटर लंबी मनमाड-इंदौर लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है, और भूमि अधिग्रहण की स्थिति और परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि धुले (बोरहीवीर) नरदाना रेलवे लाइन के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) 31.01.2019 को स्वीकृत की गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है, और भूमि अधिग्रहण की स्थिति क्या है और परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(च) बजट 2021 में घोषित नासिक मेट्रो की स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है और भूमि अधिग्रहण की स्थिति और परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): वर्तमान में, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (508 किलोमीटर) भारत में हाई स्पीड रेल की एकमात्र स्वीकृत परियोजना है जिसे जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से निष्पादित किया जा रहा है।

हाई स्पीड रेल परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी गहन होती हैं और नई परियोजना शुरू करने का कोई भी निर्णय कई कारकों जैसे तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता, यातायात की मांग और निधियों की उपलब्धता और वित्तपोषण विकल्प आदि पर आधारित होता है। वर्तमान में, रेलवे का पहली हाई स्पीड रेल परियोजना के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित है।

इंदौर-मनमाड (309 किलोमीटर, धुले-नरडाणा को छोड़कर) नई लाइन परियोजना को 16,321 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए 268 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय उपलब्ध कराय गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के लिए लगभग 170 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

धुले (बोरविहिर)-नरडाणा नई लाइन (51 किमी) परियोजना को 493 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया था। मार्च 2025 तक 187 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 के लिए 128 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के लिए आवश्यक 302 हेक्टेयर भूमि में से 293 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, नासिक मेट्रो के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बहरहाल, मेट्रो परियोजनाएँ अत्यधिक लागत वाली परियोजनाएँ हैं जिनके लिए केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर व्यापक जाँच की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन, प्रस्ताव की व्यवहार्यता और इन परियोजनाओं का दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

रेल परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, अतिलंघनकारी साधनों का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

******